पीन्स, पाकिस्तान, और दक्षिण प्रशान्त के कई राष्ट्रों के अतिरिक्त अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय आधार पर भी इस प्रश्न को उठाया है । भारत की तरह ही आस्ट्रेलिया, न्यूजीलड, अमरीका और मारिशस की सरकारों ने भी फीजी में लागू किए गए संविधान के जातीय आधार पर भेदभाव करने वाले प्रावधानों पर चिंता व्यक्त की है । भारत सरकार राजनयिक स्तर पर ऐसे आवश्यक प्रयास करती रहेगी जो फीजी में मानवाधिकार के उल्लंघनों को रोकने के लिए अपेक्षित हो जिसमें वहां के भारतीय मूल के लोगों के मानवाधिकार भी शामिल हैं ।

Memorandum to U.N. Authorities by Kashmiri Migrants

3282. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether, due to Government's failure to protect the lives and property of J&K migrants and also refusal to rehabilitate them, a strong group of Kashmiri migrants have presented memoranda to the UN authorities and US Ambassador in New Delhi seeking their intervention and help for rehabilitation;

(b) if so, what is Government's reaction in this regard; and

(c) the details of the steps contemplated by Government to protect the lives and property of migrants of J&K and also to rehabilitate them?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI SUBODH KANT SAHAY): (a) to (c) The Government have seen media reports that a group of about 100 Kashmiri migrants staged demonstration in front of United Nations High Commission for refugees at New Delhi and also in front of the U.S. Embassy, New Delhi to voice protest against continuing terrorism in Kashmir and to highlight the plight of the minorities in Kashmir Valley. They are reported to have demanded U.N. intervention for rescuing the minorities in Kashmir and should slogans.

The Government have taken stringent measures to contain and control terrorism and secessionism in the State of J&K. Every effort is being made to take care of the basic needs of the migrants till they are enabled to go back to the Valley, their economic rehabilitation on a permanent basis outside the Valley is not contemplated.

3283. *[Transferred to the 9th September, 1990]*

राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 8 का चार लेन वाला राजमार्ग बनाया जाना

3284. **श्री छोटू भाई पटेल :**
श्री राजूभाई ए० परमार :
श्री जितेंद्र लाभशंकर भट्ट :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बलसाड़ जिले में अधिक यातायात को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 8 को 4 लेन वाला राजमार्ग बनाने की आवश्यकता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि राजमार्ग को किलोमीटर 357/0 से 381/6 तक चार लेन में बदले जाने के विषय को वार्षिक योजना में शामिल कर लिया गया था किन्तु बाद में इसे 1990-91 की योजना से निकाल दिया गया था; और

(ग) इसे वार्षिक योजना से बाहर निकाले जाने के क्या कारण थे और सरकार इस राजमार्ग को कब तक 4 लेनों वाला राजमार्ग बनाने का विचार रखती है ?